अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 118 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 05 मई 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने पानी के भीतर तिरंगा फहराकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल भी गोताखोरी दल का हिस्सा थे

नई दिल्ली । अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने शनिवार को पानी के भीतर सबसे बड़ा भारतीय ध्वज फहराकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया।

यह उपलब्धि बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप पर हासिल की गई। पानी के भीतर प्रदर्शित किए गए इस तिरंगे की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर थी।

अधिकारियों के अनुसार, इस रिकॉर्ड प्रयास में लगभग 200 गोताखोरों ने भाग लिया, जिनमें वन विभाग, मरीन पुलिस के गोताखोरों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञ तैराक और निजी व्यक्ति शामिल थे। यह सफल प्रयास सुबह लगभग 10 बजे संपन्न हुआ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) भी इस डाइविंग टीम का हिस्सा थे।

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने द्वीपों को एक प्रमुख वैश्विक डाइविंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का यह प्रयास किया। पर्यटन निदेशक श्री विनायक चमाडिया ने बताया कि

इस उपलब्धि का उद्देश्य क्षेत्र की अद्वितीय समुद्री जैव विविधता को प्रदर्शित करना था

इस पहल का उद्देश्य द्वीपों को स्कूबा डाइविंग और समुद्री पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके अलावा, इस पहल के अन्य उद्देश्यों में क्षेत्र के अद्वितीय जलमग्न पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण प्रयासों को उजागर करना, सतत एवं ज़िम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना, तथा अंतरराष्ट्रीय गोताखोरों, रोमांच प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करना शामिल है।

यह कार्यक्रम क्षेत्र की अद्वितीय समुद्री जैव विविधता, स्वच्छ और पारदर्शी जल, तथा विशेष रूप से स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि माननीय उप राज्यपाल की भागीदारी प्रशासन की सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और द्वीपों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस आयोजन में प्रशिक्षित गोताखोरों, सहयोगी टीमों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया, ताकि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के दिशा–निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस पहल से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे द्वीपों की पहचान एक विश्वस्तरीय डाइविंग और इको–टूरिज़्म गंतव्य के रूप में और मजबूत होगी। (स्रोत : https://www.newindianexpress.com/)

ग्रेट निकोबार परियोजना के सामरिक महत्व का समर्थन करते हैं पूर्व एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया

पूर्व वायु मुख्य मार्शल आरकेएस भदौरिया ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में किए गए दावों को बिल्कुल गलत बताते हुए खारिज कर दिया और ज़ोर देकर कहा कि यह अत्यधिक एकीकृत पहल भारत के लिए अत्यधिक सामरिक और आर्थिक महत्व रखती है। भदौरिया की ये टिप्पणी राहुल गांधी के उस आरोप के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के कैम्पबेल बे में ग्रेट निकोबार परियोजना 'देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे गंभीर अपराधों में से एक' है।

राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस परियोजना में 160 वर्ग किलोमीटर में फैले वर्षावन में लाखों पेड़ों की कटाई शामिल होगी, इसे विकास की भाषा में लिपटा विनाश बताते हुए उन्होंने कहा था कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इन आरोपों का जवाब देते हुए भदौरिया ने पीटीआई वीडियोज को बताया कि इस तरह की चिंताएं गलत हैं।

उन्होंने कहा, "यह एक अत्यंत एकीकृत परियोजना है जो भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और स्थानीय विकास में इसकी भूमिका के साथ–साथ इसके सामरिक महत्व को समझना आवश्यक है। "भदौरिया के अनुसार, इस परियोजना में लगभग 16.2 मिलियन यूनिट कंटेनर ट्रांस–शिपमेंट क्षमता वाला एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, नागरिक और सैन्य उपयोग दोनों के लिए एक समर्पित रक्षा एन्क्लेव वाला एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, गैस और सौर ऊर्जा के मिश्रण का उपयोग करने वाला 450 मेगावाट का विद्युत संयंत्र और लगभग 6.5 लाख निवासियों को समायोजित करने में सक्षम एक नियोजित टाउनशिप शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह पहल एक स्मार्ट सिटी के विकास के उद्देश्य से क्षमता निर्माण की पहल के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, अगर हम इस परियोजना को देखें तो यह एक अत्यंत एकीकृत पहल है जिसका भारत के लिए बहुत महत्व है। हाल की घटनाओं, जैसे कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए घटनाक्रमों को देखते हुए, इसे सामरिक दृष्टिकोण से समझना बेहद जरूरी है।"

पूर्व वायु सेना प्रमुख मार्शल ने कहा, " सामरिक रूप से, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इससे हमें मलाका जलडमरूमध्य से महज 150 किलोमीटर दूर स्थित होने की क्षमता प्राप्त होगी। वायु और समुद्री दोनों क्षेत्रों में हमारी समग्र जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।"

इसके अलावा, भदौरिया ने कहा कि यह भारत की व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और आवश्यकता पड़ने पर समुद्री वातावरण पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण विकास होगा। उन्होंने आगे कहा, मलाका जलडमरूमध्य महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के लगभग 25–30 प्रतिशत व्यापार मार्ग इससे होकर गुजरते हैं, और चीन के ऊर्जा मार्ग लगभग 75 प्रतिशत तक इस पर निर्भर हैं।

भदौरिया ने कहा कि जिस तरह से इस मुद्दे को तोड़–मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, यह सुझाव देना कि आदिवासी हितों की अनदेखी की गई है या अंधाधुंध वृक्ष कटाई हो रही है, भ्रामक है।

भदौरिया ने आगे कहा, "ये सभी धारणाएं और जो कहानी गढ़ी जा रही है, वे बिल्कुल निराधार हैं।" उन्होंने कहा कि जब भी इतनी बड़ी परियोजना शुरू की जाती है, तो सभी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और उसके असर को यथासंभव न्यूनतम करने के लिए उपाय किए जाते हैं।

"मेरी जानकारी के अनुसार, कुल वन क्षेत्र का केवल 1.78 प्रतिशत ही प्रभावित होगा। आदिवासी हित सर्वोपरि हैं, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से समितियाँ गठित की जा रही हैं। आदिवासी समुदायों के दृष्टिकोण से देखें तो भविष्य में उनके विकास के अलावा और कुछ नहीं है," भदौरिया ने कहा। पीटीआई–पीके एनबी (स्रोतः द प्रिंट)

माननीय सांसद ने पुलिस भर्ती में कुछ पदों के लिए आयु सीमा मानदंड की समीक्षा का किया आग्रह

श्री विजय पुरम, 4 मई।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने अण्डमान तथा निकोबार पुलिस से वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में कुछ पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा मानदंड की समीक्षा एवं पुनः परीक्षण करने का आग्रह किया है। पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को संबोधित एक पत्र में माननीय सांसद ने पुलिस विभाग से इस विषय की तत्काल जांच करने तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित आयु सीमा मानदंड से जुड़े पहलुओं का गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके।

सांसद कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार माननीय सांसद ने अपने पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि इस मामले की शीघ्र समीक्षा कर आवश्यकतानुसार भर्ती अधिसूचना में संशोधन किया जाए, ताकि इच्छुक उम्मीदवारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उपायुक्त द्वारा स्वराज द्वीप में जन शिकायत बैठक आयोजित

श्री विजय पुरम 4 मई।

दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन द्वारा स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु जन शिकायत बैठक एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता श्रीमती पूर्वा गर्ग, आईएएस, उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान ने स्वराज द्वीप स्थित डॉल्फिन रिसॉर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में की। बैठक में पीआरआई प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसमें गोविंद नगर एवं श्याम नगर के प्रधान, वार्ड सदस्य तथा पंचायत समिति के सदस्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं अलोनिवि के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संवाद के माध्यम से स्वराज द्वीप से संबंधित विकासात्मक मुद्दों एवं जन

शिकायतों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से विचार–विमर्श हुआ, जिनमें काला पत्थर में सड़क निर्माण तथा राज्य राजमार्ग के सुधार का कार्य, काला पत्थर समुद्र तट एवं आसपास के क्षेत्रों का समग्र विकास, विजय नगर के घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, पीएमजीएसवाई सड़कों एवं गोविंद नगर में लंबित एमपीएलएडीएस सड़क की समीक्षा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन तथा होटलों की जवाबदेही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विद्यालयों/पूर्व–प्राथमिक संस्थानों के पास सह–स्थापन, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण की समीक्षा, पीएमएवाई एवं वीबी जी राम जी योजनाओं के अंतर्गत मुद्दों की समीक्षा आदि शामिल थे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ज़िला प्रशासन ने समावेशी विकास, उत्तरदायी प्रशासन तथा स्वराज द्वीप के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और आश्वासन दिया कि जन समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

द्वीपों में सेवारत शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 4 मई।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए 4 मई, 2026 से 19 जून, 2026 तक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन शिक्षा सचिव श्री एल. कुमार, आईएएस, द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक श्री

शेष पृष्ठ 4 पर

बकरी पालन से सफलता की मिसाल बने शादीपुर के प्रगतिशील किसान श्री सी. एलांगो

श्री विजय पुरम, 4 मई।

दूधलाइन, शादीपुर गांव, श्री विजय पुरम से ग्रामीण उद्यमिता और सतत पशुपालन का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है, जहां 40 वर्षीय प्रगतिशील किसान श्री सी. एलांगो ने पारंपरिक बकरी पालन को एक सफल और लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। बकरी पालन में 15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, श्री एलांगो ने अपनी पत्नी श्रीमती सुमित्रा कुमारी और भाई श्री प्रितेश शर्मा के सहयोग से एक सुव्यवस्थित बकरी पालन इकाई स्थापित की है, जो क्षेत्र के इच्छुक किसानों के लिए

एक आदर्श बन चुकी है। छोटे स्तर से शुरू हुआ यह कार्य अब एक समृद्ध उद्यम बन चुका है, जिसमें वर्तमान में 96 बकरियां हैं, जिनमें 26 नर और 70 मादा शामिल हैं।

उनकी सफलता में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग का निरंतर सहयोग महत्वपूर्ण रहा है, जिसके माध्यम से समय–समय पर पशु चिकित्सा सेवाएं, उपचार और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। इस संस्थागत सहयोग ने पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता और समग्र प्रदर्शन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।

शेष पृष्ठ 4 पर

एनसीसी कैडेट्स रैंक समारोह

श्री विजय पुरम 4 मई।

एनसीसी कैडेट्स के लिए रैंक समारोह 1 मई, 2026 को जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 50 कैडेट्स ने भाग लिया और उन्हें एनसीसी गतिविधियों में उनके समर्पण, अनुशासन और प्रदर्शन के सम्मान में रैंक प्रदान किए गए। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह समारोह श्री विजय पुरम स्थित एनसीसी आर्मी यूनिट के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर

पर जेएनआरएम के प्राचार्य, वरिष्ठ एनसीसी अधिकारी तथा स्टाफ उपस्थित थे। समारोह का समापन गर्व और प्रेरणा के साथ हुआ, जिससे कैडेट्स को अधिक ज़िम्मेदारियाँ निभाने और समाज व राष्ट्र के प्रति सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

कैम्पबेल बे में आयुष्मान आरोग्य शिविर के तहत हैंडहेल्ड एक्स–रे से की गई टीबी जांच

कैम्पबेल बे, 4 मई

आज राजीव नगर, कैम्पबेल बे स्थित ट्राइबल कम्युनिटी हॉल में हैंडहेल्ड एक्स–रे स्क्रीनिंग सुविधा के साथ आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त, कैम्पबेल बे श्री शिवम ताशी धावा तथा चेयरमैन, सीटीसी कैम्पबेल बे श्री बरनाबस मंजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही गांव के कैप्टन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

यह आयोजन डॉ. मीना नासिर, चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) के पर्यवेक्षण में किया गया। स्वास्थ्य टीम में डॉ. वाई. राजेश्वरी, चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद), एलएचवी, हेल्थ एजुकेटर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लेकर शिविर को सफल बनाया। यह शिविर टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार निकोबार से आई टीम, जिसमें ज़िला कार्यक्रम समन्वयक श्री रमेश राव तथा पीएमडीटी समन्वयक श्री एस. लोकनाथन शामिल थे, ने हैंडहेल्ड एक्स–रे यूनिट का संचालन करते हुए कैम्पबेल बे खण्ड के संवेदनशील आबादी समूह की जांच की। इस दौरान कुल 64 एक्स–रे जांच की गईं। टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत यह स्क्रीनिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसे अफ्रा बे, मकाचुआ, पिलोलू तथा पुलोपांजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा, ताकि कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में भी टीबी की शीघ्र पहचान और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य टीबी नियंत्रण गतिविधियों को सुदृढ़ करना, समय पर निदान को बढ़ावा देना तथा देश को टीबी मुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है।

ज़िला एवं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का विस्तृत कार्यक्रम जारी

श्री विजय पुरम, 4 मई

अण्डमान तथा निकोबार राज्य ओलंपिक संघ द्वारा मई एवं जून 2026 के दौरान श्री विजय पुरम में आयोजित की जाने वाली ज़िला एवं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न संबद्ध खेल संघों द्वारा किया जाएगा। संघ द्वारा जारी इस कैलेंडर के अनुसार सभी निर्धारित खेल प्रतियोगिताएं तय तिथियों पर आयोजित होंगी, जिनमें विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ी भाग लेंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना तथा राज्य स्तर पर खेलों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के अनुसार सभी आयोजन निर्धारित तिथियों एवं स्थलों पर संबंधित खेल संघों के सहयोग से संपन्न कराए जाएंगे। 30 जून को ज़िला जूनियर रग्बी 7 फुटबाल चैम्पियनशिप के लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि 29 मई, 2026 है और सम्पर्क व्यक्ति 9933248121 है। 15 से 21 मई को बैडमिंटन उच्च प्रदर्शन कोचिंग शिविर के लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि 14 मई, 2026 है और सम्पर्क व्यक्ति 9531916580 है। 30 से 31 मई को ज़िला बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि 29 मई, 2026 है और सम्पर्क व्यक्ति 9434280768 है। 6 जून को ज़िला सीनियर रग्बी 7 फुटबाल चैम्पियनशिप के लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि 5 जून, 2026 है और सम्पर्क व्यक्ति 9933248121 है तथा 13 से 14 जून को ज़िला योग चैम्पियनशिप के लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि 12 जून, 2026 है और सम्पर्क व्यक्ति 9933277452 है।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा "वॉटर बाउल अभियान" का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 4 मई।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा 30 अप्रैल को एक साथ कई स्थानों पर "वॉटर बाउल अभियान" की शुरुआत की गई। यह अभियान विभिन्न सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं प्रमुख स्थानों जैसे जीपीएस राजीव नगर, जीपीएस जेट्टी बाजार और जीपीएस कैम्पबेल बे में संचालित किया गया। इसके साथ ही मयाबंदर में वेबी स्थित पशु चिकित्सालय के अंतर्गत टुगापुर और लाल टेकरी में तथा श्री विजय पुरम में भातूबस्ती, कमांड, हैडो, मिनी बे और गाराचरामा क्षेत्रों में भी इसे एक साथ शुरू किया गया।

यह दो सप्ताह का अभियान गर्मी के कठोर महीनों के दौरान, जब जल स्रोत अत्यंत कम हो जाते हैं, आवारा पशुओं और पक्षियों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा उनके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने छात्रों को आवारा पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें विद्यालय परिसर तथा आसपास रखे गए पानी के बर्तनों को नियमित रूप से भरने के लिए प्रेरित किया। विभाग ने सभी नागरिकों, पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, दुकानदारों, बाज़ार संघों और निवासियों से इस नेक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों, कार्यालयों, दुकानों, बाज़ारों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी के बर्तन रखें और उन्हें नियमित रूप से स्वच्छ एवं ताजे पानी से भरते रहें। आपकी यह छोटी–सी पहल कई प्यासे आवारा पशुओं और पक्षियों के जीवन को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार वॉटर बाउल अभियान आगामी दो सप्ताह तक जारी रहेगा और इसे द्वीपों के अन्य स्थानों तक भी विस्तारित किया जाएगा।

हटबे पुलिस की कार्रवाई : अवैध गांजा खेती का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

हटबे 4 मई।

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस स्टेशन हटबे की टीम ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता और दक्षता का परिचय देते हुए 15 अवैध गांजा (कैनाबिस) के पौधों की बरामदगी की है, जिनका कुल वजन 120 ग्राम है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।

1 मई, 2026 को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि बिधान साना, निवासी आर.के. पुर, कटाई, वार्ड नंबर 11, लिटिल अण्डमान के घर पर अवैध रूप से गांजा–कैनाबिस के पौधों की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर प्रीतम बिहारी, प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन हटबे के नेतृत्व में पुलिस टीम का त्वरित गठन किया गया। टीम द्वारा बिधान साना के घर परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 15 अवैध गांजा के पौधे बरामद किए गए। सभी पौधों को मापकर और तौलकर उनका कुल वजन 120 ग्राम पाया गया। सभी पौधों को विधिवत ज़ब्त कर लिया गया तथा आरोपी बिधान साना, पुत्र स्वर्गीय ठाकुर दास साना (आयु 72 वर्ष) को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पूरी कार्रवाई श्री अंकित यादव, एसडीपीओ, स्वराज द्वीप के नेतृत्व में तथा श्रीमती नियति मित्तल, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण अण्डमान ज़िला के समग्र पर्यवेक्षण में संपन्न की गई।

कार निकोबार में ग्रीष्मकालीन अवकाश : विद्यार्थियों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण शुरू

कार निकोबार, 4 मई।

शिक्षा विभाग, कार निकोबार द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश 2026 के दौरान विद्यालयी छात्रों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाना है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत जीएसएसएस सवाई में हुई। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से तीन क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (सीआरसी) में आयोजित किया जा रहा है, जिनमें जीएसएसएस सवाई में 04.05.2026 से 09.05.2026 तक, 175 छात्र, जीएसएसएस मलाका में 11.05.2026 से 16.05.2026 तक, 240 छात्र, जीएसएसएस लपाती में 18.05.2026 से 23.05.2026 तक, 69 छात्र शामिल होंगे।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्लंबिंग, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ईगिरी, स्थानीय शिल्प निर्माण, चटाई बनाना, कॉयर से संबंधित गतिविधियां तथा सिलाई जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनमें संरचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उद्योग विभाग और आईटीआई कार निकोबार द्वारा तकनीकी विशेषज्ञता एवं संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ग्राम प्रधानों ने छात्रों को प्रेरित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे समुदाय की सक्रिय सहभागिता देखने को मिल रही है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल, आत्मनिर्भरता और आजीविका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी हितधारकों, विशेषकर ग्राम प्रधानों, अभिभावकों और छात्रों का आभार व्यक्त किया है।

बकरी पालन से सफलता की मिसाल

पृष्ठ 1 का शेष

वैज्ञानिक प्रजनन और प्रबंधन तकनीकों को अपनाते हुए, श्री एलांगो ने मांस की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय बाज़ार की मांग को ध्यान में रखते हुए नर बकरों का बधियाकरण जैसे उपाय लागू किए हैं। द्वीपों में बकरी के मांस की उच्च मांग को देखते हुए, इस कदम से उत्पाद की गुणवत्ता और लाभ दोनों में वृद्धि हुई है।

मांस उत्पादन के साथ–साथ, श्री एलांगो ने बकरी के दूध उत्पादन में भी विविधता लाई है। अपने पोषण और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध बकरी का दूध लगभग 150 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है, जिससे आय का एक अतिरिक्त और स्थायी स्रोत प्राप्त हो रहा है।

समर्पण, रणनीतिक योजना और कुशल प्रबंधन के माध्यम से, श्री एलांगो ने प्रतिवर्ष लगभग 6,00,000 से 7,00,000 रुपये का प्रभावशाली कारोबार हासिल किया है। उनकी यह यात्रा पशुपालन को एक सतत आजीविका विकल्प के रूप में दर्शाती है और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सफलता कहानी पारिवारिक सहयोग, उन्नत तकनीकों के उपयोग और सरकारी संस्थाओं की भूमिका को उजागर करती है, जो किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। (स्रोतः पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग)।

द्वीपों में सेवारत शिक्षकों के लिए

पृष्ठ 1 का शेष

केशव नरेंद्र सिंह सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शिक्षा सचिव श्री एल. कुमार ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में तेजी से हो रहे बदलावों के संदर्भ में शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के महत्व को विस्तारपूर्वक रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह बहुआयामी और कौशल–आधारित होती जा रही है। ऐसे में शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे समय–समय पर स्वयं को अद्यतन रखें और नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और वे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, सोच एवं भविष्य को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लें और प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का प्रभावी उपयोग अपने–अपने विद्यालयों में करें, ताकि शिक्षण के परिणामों में ठोस सुधार लाया जा सके।

इससे पूर्व, शिक्षा निदेशक श्री केशव नरेंद्र सिंह ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों, विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पहल शिक्षकों की दक्षता को बढ़ाने, शिक्षण पद्धतियों को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि शिक्षा विभाग द्वीपों के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नेल्लोर, भुवनेश्वर एवं मैसूर तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये विशेषज्ञ नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रभावी एवं आधुनिक शिक्षण रणनीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण सत्रों में विशेष रूप से शिक्षार्थी–केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण, नवाचारी एवं गतिविधि–आधारित शिक्षण पद्धतियाँ, समावेशी शिक्षा, तथा डिजिटल तकनीकों एवं उपकरणों के उपयोग पर बल दिया जाएगा। इसके माध्यम से कक्षा–कक्ष में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने, उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के कुल 2,598 शिक्षक लाभान्वित होंगे। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके और प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सके।

प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उद्घाटन सत्र का समापन राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्या श्रीमती संगीता चंद के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा संस्थान एवं डाइट के माध्यम से ऐसे निरंतर एवं संरचित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विभाग का उद्देश्य है कि इन पहलों के माध्यम से द्वीपों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा शिक्षकों को सशक्त बनाकर विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ई–कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 का सख्त अनुपालन

श्री विजय पुरम, 4 मई।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सभी संबंधित लोगों, निवासियों, संस्थानों, थोक उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, निजी संगठनों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने वाली फर्मों को यह सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई–कचरा) अपनी जगह पर मैनेज किए जाने वाले सभी ई–वेस्ट को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए ई–वेस्ट (मैनेजमेंट) नियम, 2022 के नियमों के अनुसार सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसे **https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/E-Waste/e-waste_rules_2022-pdf** पर उपलब्ध है या क्यूआर कोड स्कैन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि :

1. ऑथराइज्ड हैंडलिंग और डिस्पोजल : नियमों के तहत बताए गए किसी भी तरह के सभी ई–वेस्ट को, जो सृजन हुआ है, सिर्फ मंजूर और प्राधिकृत चैनलों के जरिए इकट्ठा और चैनलाइज किया जाएगा और भारत में कहीं भी मौजूद प्राधिकृत ट्रीटमेंट, भंडारण और डिस्पोजल सुविधाओं तक पहुँचाया जाएगा।

2. मैनिफेस्ट सिस्टम और एनओसी की जरूरत : ई–वेस्ट का परिवहन, पारदर्शिता और ट्रेसेबिलिटी पक्का करने के लिए नियमों के तहत बताए गए मैनिफेस्ट सिस्टम के तहत सख्ती से किया जाएगा। ई–वेस्ट के अंतर्राज्य परिवहन के लिए **ANPCC** से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना जरूरी है।

3. ऑथराइज्ड एंटिटीज के साथ जुड़ना : बल्क कंज्यूमर, इंस्टीट्यूशन और बिजनेस सिर्फ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर)–कम्प्लायंट रजिस्टर्ड रीसाइक्लर और **MoEF&CC** और **CPCB** से सही तरीके से ऑथराइज्ड कलेक्शन एजेंसियों के साथ ही जुड़ेंगे। अनरजिस्टर्ड या अनऑथराइज्ड हैंडलर/सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ना पूरी तरह से मना है।

4. इनफॉर्मल हैंडलिंग पर रोक : ई–वेस्ट का इनफॉर्मल कलेक्शन, तोड़ना, ठीक करना या रीसाइक्लिंग पूरी तरह से मना है और इसके लिए लागू एनवायरनमेंटल कानूनों के तहत एक्शन लिया जाएगा।

5. जरूरी रजिस्ट्रेशन और पालन : सभी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर और रीसाइकलर को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड **(CPCB)** ईपीआर पोर्टल **https://eprewaste.cpcb.gov.in** पर रजिस्टर करना होगा और ई–वेस्ट कलेक्शन और पर्यावरण के लिए सही रीसाइक्लिंग के लिए अपने तय सालाना टारगेट का पालन करना होगा।

6. पब्लिक पार्टिसिपेशन : आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गैर–कानूनी ई–वेस्ट हैंडलिंग, प्रोसेसिंग या डिस्पोजल के किसी भी मामले की रिपोर्ट **ANPCC** को **dstpcc-andamans@and.nic.in** पर ईमेल करें। ई–वेस्ट की गलत हैंडलिंग से पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसमें मिट्टी का खराब होना, हवा का प्रदूषण और नाजुक पानी के इकोसिस्टम को नुकसान शामिल है। इसलिए सभी स्टेकहोल्डर से ऊपर दिए गए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की जाती है। यह अण्डमान तथा निकोबार आइलैंड्स में पर्यावरण की सुरक्षा और ई–वेस्ट के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के हित में है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

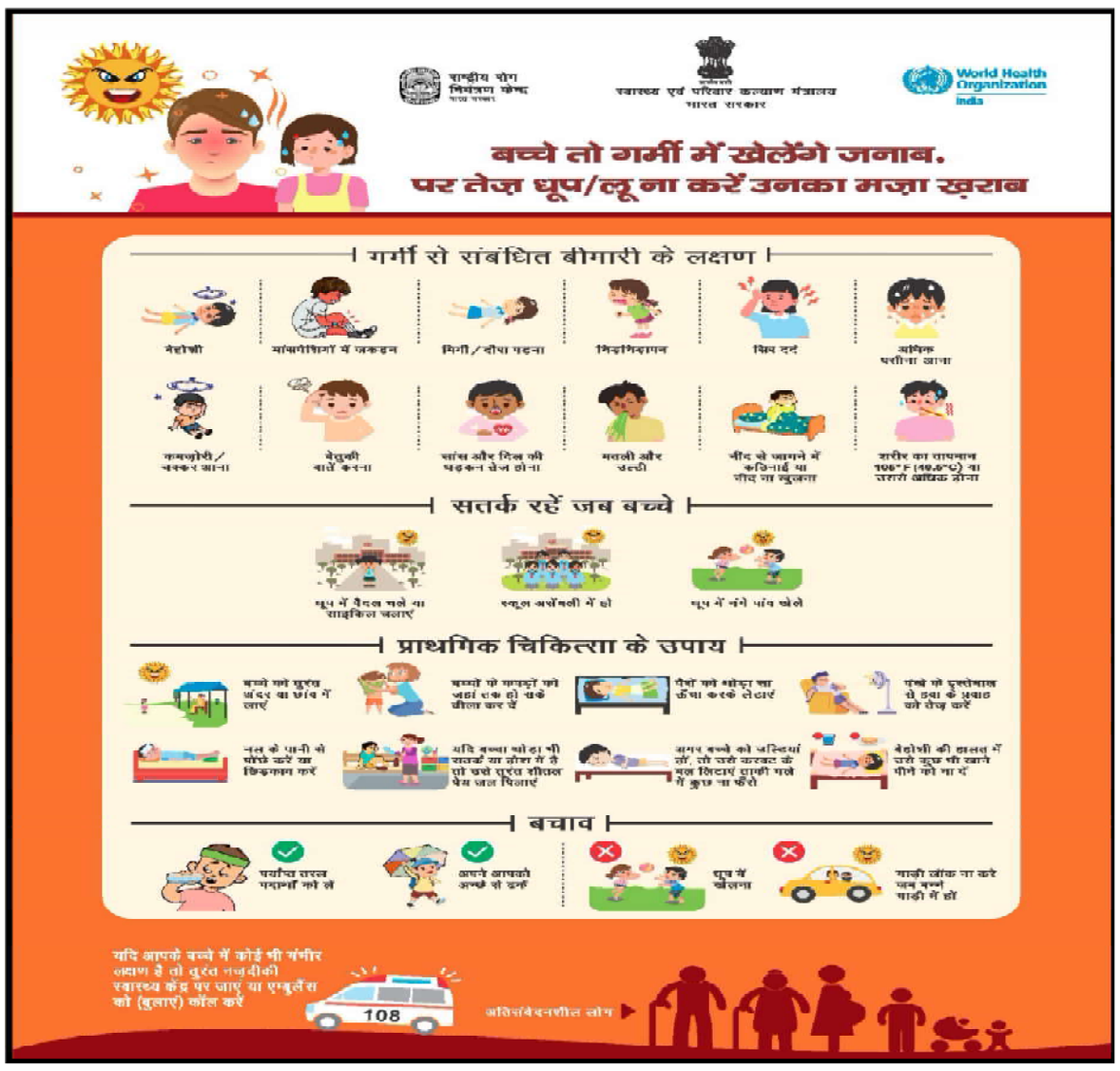

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ANDAMAN AND NICOBAR POLLUTION CONTROL COMMITTEE
Dolly Gunj, Sri Vijaya Puram. Tel.Fax.250370
Email: dstpcc-andamans@nic.in

VACANCY NOTICE

The Andaman & Nicobar Pollution Control Committee, Department of Science & Technology invites application for the posts of Computer Assistant, Junior Laboratory Assistant and Field Assistant purely on Contract Basis for a period of 01 year extendable based on performance.

For complete details of Vacancy Notice and Application Proforma, kindly visit the departments website https://dstpcc.andamannicobar.gov.in/ and A & N Administration web site https://www.andamannicobar.gov.in.

ई–निविदा आमंत्रित सूचना

सं. ई–निविदा / डी.बी. / सि.डि / 2026 / 1804 दिनांक 28.04.2026

कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रभाग, अलोनिवि, डिगलीपुर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अनुमोदित और पात्र ठेकेदारों से ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदा आमंत्रित करता है, जिसमें दो बोली प्रणाली (योग्यता और वित्तीय) होगी, जो अलोनिवि के ठेकेदार हों या सभी ठेकेदार हों, चाहे उनका अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग में पंजीकरण है या नहीं, इस शर्त के साथ कि उन्हें संबंधित कार्य के प्रदर्शन का अनुभव हो जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठनों के अनुसार आवश्यक है और उनके खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी न हो, निम्नलिखित कार्य के लिए –

1. NIT No. 76/SE/CC-I/2026-27, कार्य का नाम–एसएच–14 पर 10.364 कि.मी. पर अजीत बरई के घर के पास 6x5 मीटर (एकल सेल) आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट द्वारा क्षतिग्रस्त कल्वर्ट का पुनर्निर्माण, एसडी–।।।, सीडी, अलोनिवि, डिगलीपुर के अंतर्गत। अनुमानित लागत : रु. 1,09,69,947 / –, धरोहर राशि : 2,19,399 / –, कार्य समाप्ति की अवधि : 06 माह। (Tender ID : 2026_APWD_22866_1)

बोली–पूर्व सम्मेलन अधीक्षण अभियंता कार्यालय, निर्माण सर्किल संख्या– ।, अलोनिवि, श्री विजय पुरम के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 06 / 05 / 2026 को पूर्वाहन 11.30 बजे आयोजित किया जाएगा

निविदा पत्र और अन्य विवरण वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 14 / 05 / 2026 को अपराहन 1500 बजे तक होगी, अन्य विवरण या जानकारी वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in पर देखी जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता, नि.मं, अलोनिवि, डिग्लीपूर

ई–निविदा आमंत्रित सूचना

सं. ई–निविदा / डी.बी. / सि.डि. / 2026 / 1803 दिनांक 28.042026

कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रभाग, अलोनिवि, डिगलीपुर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अनुमोदित और पात्र ठेकेदारों से ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदा आमंत्रित करता है, जिसमें दो बोली प्रणाली (योग्यता और वित्तीय) होगी, जो अलोनिवि के ठेकेदार हों या सभी ठेकेदार हों, चाहे उनका अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग में पंजीकरण है या नहीं, इस शर्त के साथ कि उन्हें संबंधित कार्य के प्रदर्शन का अनुभव हो जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठनों के अनुसार आवश्यक है और उनके खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी न हो, निम्नलिखित कार्य के लिए–

1. NIT No. 77/SE/CC-I/2026-27, कार्य का नाम : खुदीरामपुर वार्ड संख्या 4 में आरसीसी पुल का निर्माण, एसडी–V, सीडी, अलोनिवि डिगलीपुर के अंतर्गत। अनुमानित लागत : रु. 3,10,90,235 / –, धरोहर राशि : रु. 6,21,805 / –, कार्य समाप्ति की अवधि : 10 माह। (Tender ID : 2026_APWD_22873_1)

बोली–पूर्व सम्मेलन अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, निर्माण सर्किल संख्या– ।, अलोनिवि, श्री विजय पुरम के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 06 / 05 / 2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे आयोजित किया जाएगा।

निविदा पत्र और अन्य विवरण वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 14 / 05 / 2026 को अपराहन 1500 बजे तक होगी, अन्य विवरण या जानकारी वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in पर देखी जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता, नि.मं, अलोनिवि, डिग्लीपूर

एशियाई विकास बैंक ने शुरू की एक नई वित्त पोषण सुविधा

नई दिल्ली, 04 मई।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहायता के उद्देश्य से एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। यह पहल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी में लाभ पहुंचाएगी।

महत्वपूर्ण खनिज–से–विनिर्माण वित्तपोषण साझेदारी सुविधा नामक इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण जैसे उच्च–मूल्य वाले उद्योगों के केंद्र में बदलना है।

बैंक के अनुसार, यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखलाओं में परियोजना तैयारी, नीतिगत सुधार और सार्वजनिक निवेश तथा निजी वित्तपोषण को बढावा देगी। यह कार्यक्रम विकासशील सदस्य देशों को उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सहायता के लिए शुरू किया गया है।

एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने एक बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण खनिज अगले औद्योगिक युग को आकार देंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को खनिज पदार्थों से उपलब्ध होने वाले रोजगार, प्रौद्योगिकी और मूल्य का लाभ उठाना चाहिए।

वित्तपोषण संरचना के दो मुख्य हिस्से हैं, जिसमें अनुदान और दूसरा उत्प्रेरक वित्त पर केंद्रित है। जापान ने इस योजना के लिए दो करोड अमरीकी डॉलर और ब्रिटेन ने 1 करोड 60 लाख डॉलर देने की सहमति दी है।

यह पहल क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक की 2025 रणनीति पर आधारित है। एशियाई विकास बैंक ने कहा कि वह पहले से ही भारत में बैटरी निर्माण और पुनर्चक्रण, मंगोलिया में भूवैज्ञानिक डेटा मानचित्रण तथा उज्बेकिस्तान में एआई–संचालित महत्वपूर्ण धातु उत्पादन और चक्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहा है।बैंक ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना और साथ ही पूरे क्षेत्र में समावेशी आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

अस्पतालों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने जारी किए नए अग्नि सुरक्षा दिशा–निर्देश

नई दिल्ली, 04 मई।

अस्पतालों में बढ़ते बिजली लोड और ऑक्सीजन–समृद्ध वातावरण के कारण आग लगने का खतरा अधिक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशा–निर्देशों का उद्देश्य विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नई दिशा–निर्देशों में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उन्नत और व्यवस्थित रणनीतियां शामिल की गई हैं। खासतौर पर गंभीर मरीजों, आईसीयू, एनआईसीयू और अन्य संवेदनशील वार्डों के लिए अलग से चरणबद्ध निकासी की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इन दिशानिर्देशों में फायर सेफ्टी गवर्नेंस को मजबूत करने, नियमित ऑडिट सुनिश्चित करने और अस्पताल स्टाफ को बेहतर प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि "नेशनल गाइडलाइंस ऑन फायर एंड लाइफ सेफ्टी इन हेल्थकेयर फैसिलिटीज (2026)" अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि इन दिशानिर्देशों में खास तौर पर गंभीर और चलने–फिरने में असमर्थ मरीजों के लिए फेज्ड इवैक्युएशन (चरणबद्ध निकासी) की रणनीति शामिल की गई है।

नई गाइडलाइंस में आईसीयू, एनआईसीयू (नवजात गहन चिकित्सा इकाई), पीआईसीयू (बाल गहन चिकित्सा इकाई) और ऑपरेशन थिएटर जैसे हाई–रिस्क क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, ताकि इन संवेदनशील स्थानों पर किसी भी आपात स्थिति में तेजी और सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया दी जा सके। उन्होंने सभी राज्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं से आग्रह किया कि वे नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा ऑडिट विवरण आईएचआईपी पोर्टल पर अपलोड करें, यह देखते हुए कि ऐसी प्रथाएं अनुपालन को संस्थागत रूप देंगी और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करेंगी।

भारत ने एक हफ्ते में दूसरी बार किया लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण

नई दिल्ली, 04 मई।

भारत ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार ओडिशा तट पर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी–शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने 1,500 किमी. की रेंज में निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर समुद्र में देश की सुरक्षा बढ़ाने में बड़ी उपलब्धि दिलाई। डीआरडीओ ने पिछले सप्ताह 02 मई को भी ओडिशा तट पर इसी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी–शिप मिसाइल का परीक्षण किया था।

इस टेस्ट ने मिसाइल के उन्नत टर्मिनल मार्गदर्शन प्रणाली की सटीकता को साबित कर दिया। इसने लॉन्च से लेकर आखिरी असर तक मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया, जिसमें बीच रास्ते में किए गए दांव–पेच और लगातार तेज रफ्तार से उड़ान भरना भी शामिल था। इस लॉन्ग रेंज सरफेस–टू–एयर मिसाइल (एलआर–एसएचएएम) को भारत के समुद्री तटों पर तैनात किया जाएगा। यह स्वदेशी दो–चरणों वाला सॉलिड–प्रोपेल हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह अपनी तरह का पहला और एक शक्तिशाली हथियार है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाता है।

यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जो कम ऊंचाई पर कई बार उछलते हुए एक अर्ध–बैलिस्टिक मार्ग का अनुसरण करती है, जिससे यह अपनी उड़ान के अधिकांश समय तक रडार की पकड़ से बची रहती है। यह अपने अंतिम चरण में अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सेंसर का उपयोग करते हुए स्थिर और गतिशील दोनों तरह के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे डीआरडीओ की एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी और अलग–अलग औद्योगिक भागीदारों ने विकसित किया है।

SACHET क्या है? अब खतरे से पहले बजेगा आपके फोन पर अलर्ट, सरकार का नया सिस्टम बचाएगा जान

नई दिल्ली, 04 मई।

अगर शनिवार को आपके स्मार्टफोन पर अचानक तेज बीप की आवाज आई थी तो घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, यह भारत सरकार की ओर से एक नए आपदा चेतावनी सिस्टम की टेस्टिंग का हिस्सा था. इसका मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति में करोड़ों लोगों तक कुछ ही सेकंड में अलर्ट पहुंचाया जा सके ताकि समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके.

SACHET एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसे खासतौर पर प्राकृतिक और मानव–निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों को तुरंत सूचना देने के लिए तैयार किया गया है. इस सिस्टम को Centre for Development of Telematics ने विकसित किया है जो कि दूरसंचार विभाग के अंतर्गत काम करता है. वहीं, इसे National Disaster Management Authority के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है.

यह सिस्टम कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीक है. इसका फायदा यह है कि अलर्ट मैसेज तेज, भरोसेमंद और एक समान फॉर्मेट में सभी डिवाइस और नेटवर्क पर पहुंचते हैं.

SACHET की सबसे खास बात यह है कि यह आपके लोकेशन के आधार पर अलर्ट भेजता है. यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को संदेश मिलेगा जो किसी संभावित खतरे वाले इलाके में मौजूद हैं. इससे अनावश्यक घबराहट कम होती है और सही लोगों तक सही समय पर जानकारी पहुंचती है.

अब तक यह सिस्टम मुख्य रूप से SMS के जरिए अलर्ट भेजता रहा है लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए Cell Broadcast तकनीक भी जोड़ी जा रही है. इस तकनीक के जरिए एक तय क्षेत्र में मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है जिससे नेटवर्क पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और अलर्ट तेजी से पहुंचता है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस सिस्टम के जरिए अब तक अरबों मैसेज भेजे जा चुके हैं. ये अलर्ट करीब 19 भारतीय भाषाओं में जारी किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भाषा में चेतावनी को समझ सकें. इसमें चक्रवात, बाढ़, खराब मौसम और अन्य आपात स्थितियों से जुड़ी जानकारी शामिल रही है.

हाल ही में देशभर में इस सिस्टम की बड़े स्तर पर टेस्टिंग की गई, जिसमें लोगों को अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में अलर्ट मैसेज मिले. ये सिर्फ ट्रायल थे ताकि सिस्टम की क्षमता और पहुंच को परखा जा सके. इसलिए ऐसे मैसेज मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है.

यह नया सिस्टम दिखाता है कि भारत अब आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है. आने वाले समय में SACHET जैसे प्लेटफॉर्म लोगों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

इतिहास के पन्नों में 05 मईः संगीत सम्राट नौशाद की पुण्यतिथि, संघर्ष से शिखर तक का सफर

नई दिल्ली, 04 मई।

इतिहास के पन्नों में 05 मई की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है। इसी दिन महान संगीतकार नौशाद अली की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 05 मई 2006 को दुनिया को अलविदा कहने वाले नौशाद अली का जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है।

संगीत के प्रति गहरी लगन के चलते वे अपने घर लखनऊ से निकलकर मुंबई पहुंचे, जहां शुरुआती दिनों में उन्हें फुटपाथ पर रहकर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने सोना, खाना और काम की तलाश–सब कुछ किया। धीरे–धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें उस्ताद झंडे खान के साथ काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें मात्र 40 रुपए मासिक वेतन मिलता था। लेकिन यही अवसर उनके करियर की मजबूत नींव साबित हुआ।

नौशाद के जीवन का टर्निंग पॉइंट 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा रही। इस फिल्म के संगीत ने उन्हें रातों–रात प्रसिद्धि दिलाई। फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

उन्होंने कई ऐतिहासिक और यादगार फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें मुगल–ए–आजम, मदर इंडिया, कोहिनूर, पाकीजा, गंगा जमुना, बाबुल और मेरे महबूब जैसी फिल्में शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 1981 में देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नौशाद अली का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1949– भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई।

1961– अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री कमांडर ऐलन शेपर्ड अपने अंतरिक्ष यान से अटलांटिक महासागर में उतरे। उन्हें एक हेलिकॉप्टर ने पानी से बाहर निकाला और शेपर्ड ने अपनी इस यात्रा को शानदार सैर करार दिया।

1999– रोजाने प्रोदी यूरोपीय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने।

1980– लंदन में स्थित ईरानी दूतावास को कुछ हमलावरों के कब्जे से आजाद कराया गया। ब्रिटिश एसएएस कमांडो ने पांच हमलावर ईरानी बंदूकधारियों को मार डाला और एक को हिरासत में लेकर इस नाटक का अंत किया।

2003– भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू, बेल्जियम में गुय वेरहोफ्सराड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पतन।

2005– ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला।

2008– पद्मविभूषण पं. किशन महाराज का अन्तिम संस्कार सम्पन्न।

2008– एनटीपीसी के रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीनटेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड मिला।

2008– डिस्पोजल सीरिंज के आविष्कारक न्यूजीलैंड के कोलिन मार्डोक का निधन।

2010 – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने सभी कोर्सों में सेक्स वर्कर्स और उनके आश्रितों की फीस माफ करने की घोषणा की।

2017– इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साउथ एशिया सैटेलाइट।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ा फ्री–लिविंग अमीबा का खतरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

नई दिल्ली, 04 मई।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मुक्त–जीवी अमीबा (फ्री–लिविंग अमीबा) अब वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बढ़ता खतरा बन रहे हैं। बढ़ते तापमान, पुरानी जल आपूर्ति व्यवस्था और कमजोर निगरानी प्रणाली के कारण इनका फैलाव तेज हो रहा है।

ये सूक्ष्म जीव मिट्टी, ताजे पानी और कई बार मानव निर्मित जल प्रणालियों में पाए जाते हैं। अधिकांश अमीबा हानिरहित होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां गंभीर और जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकती हैं। ऐसा ही एक खतरनाक अमीबा है नेगलेरिया फाउलेरी, जिसे आम तौर पर "दिमाग खाने वाला अमीबा" कहा जाता है। यह दूषित पानी के नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कर सीधे मस्तिष्क तक पहुंच सकता है और तेज गति से जानलेवा संक्रमण पैदा करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन अमीबाओं की सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये बहुत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये अधिक तापमान, क्लोरीन जैसे रसायनों और पानी की आपूर्ति प्रणालियों में भी टिके रह सकते हैं, जिससे इन्हें खत्म करना मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा, ये अमीबा अन्य खतरनाक जीवाणुओं और वायरस को अपने अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। इसे "ट्रोजन हॉर्स प्रभाव" कहा जाता है, जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव अमीबा के भीतर छिपकर बच जाते हैं और बाद

में फैल सकते हैं। इससे संक्रमण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या भी बढ़ सकती है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन इस खतरे को और बढ़ा रहा है। गर्म पानी में ये अमीबा तेजी से बढ़ते हैं, जिससे नए क्षेत्रों में भी इनका फैलाव हो सकता है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए विशेषज्ञों ने बेहतर निगरानी प्रणाली, उन्नत जल शोधन तकनीक और स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जल प्रबंधन के संयुक्त प्रयास (वन हेल्थ दृष्टिकोण) अपनाने की जरूरत बताई है।

कुल मिलाकर, यह खतरा भले ही आंखों से दिखाई न दे, लेकिन इसका असर वैश्विक स्वास्थ्य पर गंभीर हो सकता है। –(इनपुटःएजेंसी)

भारत को मिलेगी एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट; पिक्सेल और सर्वम ने की साझेदारी

नई दिल्ली, 04 मई।

भारत में एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट विकसित करने के लिए स्पेस–टेक फर्म पिक्सेल और एआई स्टार्टअप सर्वम ने साझेदारी की है। यह जानकारी दोनों कंपनियों की ओर से सोमवार को दी गई। इस साझेदारी के तहत पिक्सेल पाथफाइंडर सैटेलाइट को डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण और संचालित करेगी, जबकि सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का आधार प्रदान करेगी, जिससे ऑनबोर्ड चलने वाले फुल–स्टैक लैंग्वेज मॉडल के माध्यम से सीधे कक्षा में प्रशिक्षण और अनुमान दोनों संभव हो सकेंगे।

200 किलोग्राम श्रेणी की सैटेलाइट पाथफाइंडर, जिसके 2026 की चौथी तिमाही तक कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है, अंतरिक्ष–आधारित कंप्यूटिंग क्षमताओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों के प्रयासों को दिखाता है। कम शक्ति वाले प्रोसेसर पर निर्भर पारंपरिक सैटेलाइट सिस्टम के विपरीत, पाथफाइंडर में स्थलीय एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर में उपयोग किए जाने वाले डेटा सेंटर–स्तरीय जीपीयू होंगे, जो अंतरिक्ष में सीधे उच्च–प्रदर्शन कंप्यूटिंग को सक्षम बनाएंगे।

इस सैटेलाइट में पिक्सल का प्रमुख हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा भी लगा होगा, जिससे यह दुनिया के उन पहले सैटेलाइट्स में से एक बन जाएगा जो उच्च–रिजॉल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा कैप्चर करने और उन्नत एआई मॉडल का उपयोग करके कक्षा में ही उसका विश्लेषण करने में सक्षम है।

इससे पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में कच्चा डेटा भेजने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे रियल टाइम में जानकारी प्राप्त करना, तेज निर्णय लेना और पर्यावरण निगरानी, संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की निगरानी जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग संभव हो सकेगा।

पिक्सेल के सीईओ अवैस अहमद ने कहा कि ऊर्जा, भूमि और विस्तार क्षमता से संबंधित बाधाओं के कारण जमीनी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑर्बिटल डेटा सेंटर एक नया आयाम प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित और डेटा स्रोतों के निकट स्थित अंतरिक्ष–आधारित कंप्यूटिंग कई सीमाओं को दूर कर सकती है।

सर्वम के सीईओ प्रत्युष कुमार ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी के स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म को स्थलीय प्रणालियों से आगे अंतरिक्ष तक विस्तारित करती है, जिससे भारत में निर्मित एआई मॉडल विदेशी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर से स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑर्बिट में स्वदेशी इंटेलिजेंस का निर्माण तकनीकी संप्रभुता की कुंजी है।

यह मिशन कठोर अंतरिक्ष वातावरण में वास्तविक समय एआई अनुमान, विद्युत प्रबंधन, तापीय प्रदर्शन और डेटा वर्कफ्लो का भी परीक्षण करेगा, जिससे भविष्य के एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सिस्टम्स की नींव रखी जाएगी। सैटेलाइट का विकास पिक्सेल की आगामी गीगापिक्सल सुविधा में किया जाएगा, जिसे 100 सैटेलाइट्स तक उत्पादन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर को एक वर्ष पूरा, रक्षा मंत्री ने कहा–हमें सिर्फ एक्टिव ही नहीं रहना है, बल्कि प्रोएक्टिव भी रहना

नई दिल्ली, 04 मई।

ऑपरेशन सिंदूर का एक वर्ष पूरा हो चुका है। जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, तो सेनाओं का शौर्य याद आता है। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को जो मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया, उससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ये तो फिर भी अच्छा हुआ कि हमने धैर्य दिखाते हुए, केवल आतंकवादियों को ही नेस्तनाबूत किया, नहीं तो हमारी सेनाएं क्या कुछ करने में सक्षम है, इसका अंदाजा तो पूरी दुनिया को है। सोमवार को यह बात रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कही।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का एक उदाहरण था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल सिस्टम के साथ–साथ, अनेक आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया गया। इसने यह साबित किया कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उपयोग भी कर रही हैं। रक्षामंत्री सोमवार को भारतीय सेना के 'नॉर्थ टेक सिम्पोजियम' में बोल रहे थे। इस सिम्पोजियम को आयोजित करने का उद्देश्य रक्षा त्रिवेणी संगम है। यानी जहां तकनीक, उद्योग और सैनिक एक साथ एक मंच पर मिल रहे हैं।

यहां बोलते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि अगर हम युद्ध प्रणाली को देखें, तो पहले के समय में, कम से कम हमें इस बात का मोटा–मोटा अंदाजा होता था कि सामने वाला क्या कर सकता है। उसकी सैन्य क्षमता, उसके प्लेटफार्म , उसकी डॉक्ट्रिन, इन सबका अंदाजा होता था। लेकिन अब, लगातार एक ऐसा चौंकाने वाला तत्व सामने आ रहा है, जिसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। जिन चीजों को हम सामान्य नागरिक जीवन का हिस्सा मानते थे, वे अब घातक हथियारों में बदल रही हैं।

रक्षामंत्री ने कहा कि हमें सिर्फ एक्टिव ही नहीं रहना है,

बल्कि प्रोएक्टिव भी रहना है। हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार भी रहना है उन्होंने बताया कि हमारी सेनाओं ने और हमारी उद्योगों ने बदलती हुई परिस्थितियों का बहुत अच्छे से आकलन किया है। उन्होंने कहा कि इनकी तैयारी बिलकुल सटीक रहती है। इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में तो ऑपरेशन सिंदूर ही हमारे सामने है। उन्होंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में इन प्रयासों का असर दिख भी रहा है।

आकंड़े बताते हैं, हमारा घरेलू रक्षा उत्पाद, वित्त वर्ष 2025–26 में, 1 लाख 54 हजार करोड़ रूपए के रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंच गया। वहीं डिफेंस निर्यात भी, 2025–26 में 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकडे तक पहुंच गया। इसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर का बड़ा अहम योगदान रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम जो इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है। रक्षा आर एंड डी बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा इंडस्ट्री, शिक्षा जगत और स्टार्टअप के लिए आवंटित कर दिया गया है। अब तक इन सभी के द्वारा लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का उपयोग भी किया जा चुका है।

सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल ऋण स्वीकृति पत्र का किया खंडन

नई दिल्ली, 04 मई।

सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर ऋण स्वीकृति पत्र दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में साढे तीन सौ रुपये प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान पर 5 लाख रुपये का ऋण देने का झूठा वादा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बनाया गया है।

कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुद्रा योजना व्यक्तियों या सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे ऋण प्रदान नहीं करती है। सरकार ने ऐसी फर्जी खबरों से सावधान रहने का आग्रह किया है और लोगों को परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे संदेशों के आधार पर धन हस्तांतरण न करें और न ही व्यक्तिगत तथा बैंकिंग जानकारी साझा करें।

देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग 70 फीसदी तक बहाल

नई दिल्ली, 04 मई।

सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में एलपीजी वितरकों के पास घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कोई कमी नहीं हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई लगभग 70 फीसदी तक बहाल हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर–मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि अप्रैल महीने में 2.15 लाख टन से ज्यादा कमर्शियल एलपीजी बेची गई है। ऑटो एलपीजी की बिक्री अब तक लगभग 11,100 टन तक पहुंच गई है। इस महीने के दौरान 23 लाख से ज्यादा 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर बेचे गए हैं। इसके साथ ही 3 अप्रैल से अब तक 10,000 से ज्यादा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी), असीम आर. महाजन ने बताया कि विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया क्षेत्र के खाड़ी इलाके में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार करीब से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। महाजन ने बताया कि जानकारी साझा करने और अपने प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए हम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। महाजन ने बताया कि सऊदी अरब और ओमान के विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के अलग–अलग शहरों के लिए उड़ानें चल रही हैं, जबकि कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला हुआ है।

गैस सिलेंडर डिलीवरी से लेकर एटीएम से कैश निकासी तक, बदल गए ये बड़े नियम

नई दिल्ली, 04 मई।

नए महीने की शुरुआत के साथ ही (1 मई 2026) से देशभर में कई अहम नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और डिजिटल सुरक्षा तीनों पर पड़ेगा। किचन के बजट से लेकर बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तक, कई नई व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं।

महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में करीब 993 रूपए तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ाई गई, लेकिन होटलों–रेस्टोरेंट्स की लागत बढ़ने से बाहर खाना महंगा हो सकता है।

अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए नियम के तहत डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) यानी OTP अनिवार्य कर दिया गया है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला कोड बताए बिना सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसका मकसद चोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना है।

Reserve Bank of India की मंजूरी के बाद बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। तय फ्री लिमिट (आमतौर पर 5 ट्रांजैक्शन) के बाद हर अतिरिक्त निकासी पर करीब 23 रूपए शुल्क देना होगा। साथ ही, HDFC Bank और Bandhan Bank जैसे बैंक अब UPI के जरिए कैश निकासी को भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिन रहे हैं। बैलेंस कम होने पर फेल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लग सकता है।

डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए UPI

सिस्टम में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ PIN से काम नहीं चलेगा. टू–स्टेप वेरिफिकेशन लागू किया जा सकता है, जिसमें बायोमेट्रिक या अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इससे ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर 33 रूपए प्रति लीटर की ड्यूटी तय की है। हालांकि घरेलू एयरलाइंस के लिए कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे हवाई किराए स्थिर रहने की उम्मीद है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव किया है। अब रेंट, बिजली–पानी जैसे यूटिलिटी बिलों पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाए जा सकते हैं या इन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। इससे कार्ड यूजर्स को पहले जितना फायदा नहीं मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भी 1 मई से नए नियम लागू हो गए हैं। अब गेम्स को 'मनी गेम्स', 'सोशल गेम्स' और 'ई–स्पोर्ट्स' में बांटा जाएगा। जिन गेम्स में पैसे का लेनदेन होता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

अब सस्ती फ्लाइट्स भी खोज कर देगा ChatGPT, जानिए पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली, 04 मई।

ऑनलाइन ट्रैवल सर्च को और आसान बनाने के लिए Skyscanner ने ChatGPT के साथ साझेदारी की है। इस नई सुविधा के जरिए यूजर्स अब सीधे ChatGPT के अंदर ही फ्लाइट्स सर्च, कीमतों की तुलना और यात्रा का समय चेक कर सकते हैं। यह इंटीग्रेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं या आखिरी समय में सस्ती फ्लाइट ढूंढना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहां दिखाई जाने वाली जानकारी लाइव अपडेट होती है, जिससे यूजर्स को हमेशा ताजा कीमतें और विकल्प मिलते हैं।

ChatGPT के जरिए फ्लाइट सर्च करने के लिए यूजर्स को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले ChatGPT ऐप या वेबसाइट में लॉग–इन करें। इसके बाद मेन्यू में जाकर Apps सेक्शन खोलें और Skyscanner को एक्टिवेट करें।

फिर एक नया चैट शुरू करें और अपनी जरूरत के मुताबिक सर्च लिखें, जैसे."दिल्ली से लंदन के लिए अगले महीने की सबसे सस्ती फ्लाइट बताएं।" इसके बाद एआई टूल आपको तुरंत कई विकल्प दिखा देगा, जिनमें कीमत, एयरलाइन और यात्रा समय जैसी पूरी जानकारी शामिल होगी।

इस फीचर की मदद से यूजर्स एक ही जगह पर कई फ्लाइट ऑप्शन्स देख सकते हैं और आसानी से उनकी तुलना कर सकते हैं। अगर आप अपनी सर्च में बदलाव करना चाहते हैं, तो सिर्फ चैट में नया निर्देश देना होगा. पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती।

इसके अलावा, यह टूल अलग–अलग एयरलाइंस से डेटा लेकर लगातार अपडेट रहता है, जिससे आपको हमेशा सही और ताजा जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, अब यूजर्स एक ही चैट के भीतर फ्लाइट्स के साथ होटल और कार रेंटल जैसी सेवाएं भी सर्च कर सकते हैं। इस नए फीचर के साथ ट्रैवल प्लानिंग पहले से कहीं ज्यादा तेज, सरल और स्मार्ट हो गई है।

बढ़ती गर्मी के बीच देश की ये जगहें अब भी हैं कूल–कूल, जानें कहां है सबसे कम टेंपरेचर?

नई दिल्ली, 04 मई।

देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है. अप्रैल के आखिरी दिनों में ही कई शहरों का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था. हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में भारत के कई शहर शामिल है, जो इस बढ़ती गर्मी की गंभीरता को दिखाता है. ऐसे में लोग राहत पाने के लिए ठंडी और सुहावनी जगह की तलाश कर रहे हैं. इस बीच चलिए आज हम आपको बताते हैं देश के कुछ ऐसे हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल जहां गर्मी में भी मौसम काफी ठंड और आरामदायक बना रहता है. यहां की ठंडी हवाएं और प्रा.तिक खूबसूरती लोगों को गर्मी से राहत देती है.

अगर गर्मी से बचाना है, तो पहाड़ी इलाकों का रुख करना सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है. मनाली इस लिस्ट में सबसे आगे है यहां का तापमान आमतौर पर 25 डिग्री के आसपास रहता है, जो इस गर्मी से राहत पाने के लिए परफेक्ट बनाता है. बर्फ से ढकी चोटियों और ठंडी हवा यहां आने वालों को सुकून देती है. इसी तरह शिमला भी गर्मियों में लोगों की पहली पसंद बना रहता है. यहां की ठंडी हवाएं, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और मॉल रोड की रौनक पर्यटकों को आकर्षित करती है. जाखू मंदिर और टॉय ट्रेन का सफर इस जगह को और खास बना देते हैं.

दक्षिण भारत की बात करें तो मुन्नार एक बेहतरीन समर डेस्टिनेशन है. यहां के चाय के बागान, हरियाली और ठंडी हवा इसे खास बनाते हैं. नेचर लवर्स और कपल्स के लिए

यह जगह काफी पसंद की जाती है. वहीं उंटी को हिल स्टेशन की रानी भी कहा जाता है, यहां के गार्डन, झीलें और ठंडा मौसम गर्मी से पूरी तरह राहत देते हैं. फैमिली ट्रिप और हनीमून के लिए यह शानदार ऑप्शन माने जाते हैं.

अगर आप राजस्थान या यहां के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो माउंट आबू गर्मियों में आपके लिए सबसे नजदीकी कूल डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां का मौसम बाकी राजस्थान के मुकाबले काफी ठंडा रहता है. नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर और सनसेट पॉइंट यहां के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं. ऐसे में गर्मियों के मौसम में आप यहां घूमने जा सकते हैं.

दिल्ली की भयंकर गर्मी से बचने के लिए लोग दिल्ली के आसपास भी घूमने जा सकते हैं. गर्मियों में दिल्ली के आस पास मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश जैसी जगह पर घूमने जा सकते हैं. मसूरी की ठंडी हवाएं, नैनीताल की झीले और ऋषिकेश का शांत माहौल गर्मी से राहत देने के साथ–साथ सुकून भी देते हैं.

जिंक से प्रोटीन–फाइबर तक, पोषक तत्वों से भरपूर काला नमक चावल, सेहत के लिए अनगिनत फायदे

नई दिल्ली, 04 मई।

आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग सामान्य चावल की जगह पौष्टिक विकल्प तलाश रहे हैं। इन्हीं में से एक है काला नमक चावल। यह बेहद पौष्टिक, सुगंधित और स्वादिष्ट चावल है जो कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस चावल को 'बुद्धा राइस' या इसे 'महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद' भी कहा जाता है।

इस चावल की खासियत यह है कि यह न सिर्फ पौष्टिक बल्कि स्वादिष्ट भी है। इसमें प्राकृतिक सुगंध होती है, जिससे खाना और भी स्वादिष्ट बन जाता है। इसे दाल, सब्जी, सलाद के साथ खाया जा सकता है। इसकी खिचड़ी भी सेहतमंद होती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक जीवनशैली में पौष्टिक अनाजों को अपनी थाली में शामिल करना जरूरी है। काला नमक चावल सामान्य सफेद चावल का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। हालांकि, किसी भी नए खाद्य पदार्थ को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह अवश्य लें।

काला नमक चावल में आयरन, जिंक, प्रोटीन और फाइबर समेत अन्य पोषक तत्व भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काला नमक चावल डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। इससे डायबिटीज के मरीज आसानी से अपना खान–पान संतुलित रख सकते हैं।

इस चावल के नियमित सेवन से वजन प्रबंधन में भी मदद

मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे अनावश्यक भूख नहीं लगती और वजन बढ़ने की समस्या कम होती है। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। काला नमक चावल पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण यह कब्ज जैसी आम समस्याओं से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।

इसके अलावा, यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी है। आयरन और जिंक जैसे तत्व शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। इससे हृदय संबंधी जोखिम कम होते हैं। काला नमक चावल बच्चों और महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है। आयरन की भरपूर मात्रा एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या को दूर करने में सहायक है। जिंक इम्युनिटी बढ़ाता है और प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।–आईएएनएस